Bank Supervision Mission visited the earthquake affected areas of Maharashtra between April 30-May 10, 1995.

(b) The World Bank Mission, in its Aide-Memoire has stated that the repair and strengthening of houses by beneficiaries has got off to a good start and the current pace needs to be maintained and multiplied to meet the completion target. The relocation of 52 villages is also progressing well. The credit disbursements are low due to low expenditures and concerted action is required to accelerate its pace.

(c) The Earthquake Rehabilitation Programme is a comprehensive programme and includes, in addition to repair and the reconstruction of the damaged houses and other infrastructure, the economic and social rehabilitation of the affected areas.

Comprehensive Crop Insurance Scheme

746. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are considering to modify the Comprehensive Crop Insurance Scheme to cover all risks due to natural calamities instead of merely acting as an indemnity towards the institutional loans secured by farmers for their seasonal crops upto 10,000/- only;

(b) whether the modified Scheme is being extended to all kinds of agricultural crops instead of restricting it only to certain selective crops and the Comprehensive Scheme is being formulated and implemented urgently; and

(c) if so, whether any funds are also allocated to the States for this purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (c) The existing Comprehensive Crop Insurance Scheme covers all risks due to natural calamities. The scheme presently covers loanee farmers only. Modification of the existing scheme to increase the coverage of crops and farmers and provide greater protection to farmers against natural calamities is under the consideration of the Government.

मध्य प्रदेश के उर्वरक एककों को राजसहायता

747. श्री दिलीप सिंह भूरिया: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश के उर्वरक एककों को कितनी राजसहायता प्रदान की गई;

(ख) इसका वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान उक्त एककों को कितनी राजसहाता उपलब्ध कराने का विचार है;

(घ) क्या यह राशि अन्य राज्यों को उपलब्ध करायी गई राजसहायता की तुलना में अपर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो): (क) और (ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में स्थित विनिर्माता एककों को नियंत्रित उर्वरकों पर राजसहायता के रूप में क्रमशः 197.07 करोड़ रुपए और 167.02 करोड़ रुपए की राशि दी गयी है। नियंत्रित मुक्त उर्वरकों की बिक्री पर विशेष रियायत की योजना के अंतर्गत 1993-94 के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग ने इन उर्वरकों के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान देने के लिए कृषि एवं मध्य प्रदेश राज्य को 31.92 करोड़ की राशि दी थी। 1994-95 के दौरान कृषि तथा सहकारिता विभाग ने नियंत्रणमुक्त उर्वरकों को आपूर्तिकर्ताओं को सीधे 26.42 करोड़ तक की अदायगियां की।

(ग) से (ङ) नियंत्रित उर्वरकों पर राजसहायता की अदायगी के लिए 1995-96 के लिए बजट में 37.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नियंत्रण मुक्त उर्वरकों पर विशेष रियायत के लिए 1995-96 में किया गया बजटीय प्रावधान 1500 करोड़ रुपए है। राजसहायता का आवंटन राज्यवार अथवा जिलावार नहीं किया जाता है। राजसहायता एककों को उत्पादन तथा प्रेषित मात्रा के उनके स्तर के आधार पर दी जाती है।